RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 13 फरवरी 2024 वर्ष 05 अंक 292 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन पर पथराव

मुंबईः गुजरात के सूरत से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन पर रविवार देर रात महाराष्ट्र के नंदुरबार के पास पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक, रविवार रात आठ बजे आस्था स्पेशल ट्रेन को सूरत से रवाना किया गया था। ट्रेन में कुल 1340 यात्री सवार थे। रात करीब 10:45 बजे नंदुरबार के पास उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव किया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

नंदुरबार के पुलिस उपाधीक्षक संजय महाजन ने कहा कि हमले के दौरान कुछ यात्रियों ने तुरंत खिड़की के शीशे बंद कर दिए, लेकिन कुछ पत्थर कोच के अंदर गिरे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरूआती जांच के बाद पुलिस ने देर रात ट्रेन को नंदुरबार रेलवे स्टेशन से रवाना किया।

इससे पहले रविवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सूरत सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सूरत से अयोध्या धाम 'आस्था' स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं थीं। इस बीच बीते शुक्रवार को जालंधर से बड़ी संख्या में भगवान राम भक्त 'आस्था स्पेशल ट्रेन' से अयोध्या रवाना हुए थे।

पार्टी छोड़ने के एलान पर भड़की कांग्रेस

मुंबईः लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक च''ाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ने का एलान किया है.

कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़ा झटका मिल रहा है। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं। वैसे-वैसे पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण ने राज्य में पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। उनके इस्तीफा देने पर कांग्रेस का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर जांच एजेंसियों का दबाव है।

कांग्रेस ने बुलाई बैठक

2024 लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में शुरू हुए इस्तीफों को रोकने के लिए आलाकमान डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। एक महीने के अंदर तीन बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी अब हर हाल में यह सिलसिला रोकना चाहती है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद दिल्ली तक हलचल है। पार्टी में सबकुछ ठीक करने के लिए 13 जनवरी को पार्टी के विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि काफी नेता संपर्क में हैं तब कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से विधायकों की बैठक को कई नजरिए से देखा जा रहा है। इस बैठक में यह तय होने की उम्मीद है कि पार्टी में क्या कोई बड़ी टूट होने वाली है, या फिर बीजेपी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। कांग्रेस की बैठक में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऊपर भी नजरें रहेंगी? बाबा सिद्दीकी के अजित पवार की अगुवाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद जीशान ने अपने कांग्रेस से रिश्ते को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। वे मुंबई युवा कांग्रेस के प्रमुख भी हैं।

अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चव्हाण ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि अशोक चव्हाण ने किस मजबूरी में कांग्रेस का साथ छोड़ा।

चव्हाण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बुलाई बैठक

उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसा व्यक्ति ऐसा कदम उठाएगा। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अशोक चव्हाण के इस तरह का कदम उठाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से कोई और अशोक चव्हाण के रास्ते पर जाएगा। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण के साथ बालासाहेब थोराट और नसीम खान भी थे।

अशोक चव्हाण के इस्तीफे पर महाविकास आघाड़ी नेता भी सकते हैं। गठबंधन में शामिल शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने अशोक चव्हाण के इस्तीफे की तुलना एक बेटे का अपनी मां को छोड़ने से की है। राउत ने कहा कि अगर 1975 से 1977 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कद्दावर नेता शंकरराव चव्हाण का बेटा कांग्रेस छोड़ता है, तो यह एक बेटे का अपनी मां को छोड़ने जैसा है।

मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई... सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के 22 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी एऊ की मुम्बई में नामी बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुम्बई और नवी मुम्बई में 22 लोकेशन पर जांच एजेंसी की तरफ से छापेमारी की गयी है. सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर 7 फरवरी को भी छापेमारी की गयी थी. रेड में साढ़े 27 लाख रुपये कैश, करोड़ों की एफडी और प्रोपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं. कुल 30 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति के कागजात और कैश बरामद हुए हैं. तलोजा पुलिस स्टेशन और चेम्बूर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 अलग-अलग FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत यह कार्रवाई की है. जांच में सामने आया है कि बिल्डर टेकचंदानी व अन्य ने तलोजा और चेम्बूर में हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर करीब 1700 ग्राहकों से 400 करोड़ रुपये लिए हैं.

कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अशोक चव्हाण पर संजत राऊत ने किया कटाक्ष

मुंबईः सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अशोक चव्हाण पर कटाक्ष करते हुए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने आश्चर्य जताया कि क्या अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री इस पद पर दावा पेश करेंगे। सबसे पुरानी पार्टी और उसका 'हाथ' चिन्ह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना) और उनके उपमुख्यमंत्री अजित पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के साथ समानताएं बनाते हुए, जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों से अलग होने के बाद सेना पार्टी के प्रतीक पर अपना दावा पेश किया और जीता, राउत ने कहा कि ऐसा परिदृश्य संभव था। ''मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता।

कल तक वे एक साथ थे, चर्चा कर रहे थे; आज वह चले गए॥ क्या चव्हाण, एकनाथ मिंधे और अजीत पवार की तरह, अब कांग्रेस पर दावा करेंगे और 'हाथ' चिन्ह लेंगे? और क्या चुनाव आयोग उन्हें देगा हमारे देश में कुछ भी हो सकता है!' कहते हुए देखा गया ''जो डर गया, संजो मर गया'' (जो डरता है वह मरा हुआ माना जाता है)।

कांग्रेस नेता ने चव्हाण की अगस्त 2023 की पोस्ट को टैग करते हुए लिखा, ''सच'', जिसमें पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य के रूप में चुने जाने पर आभार व्यक्त किया था।

बेटे ने तलाक के लिए मां को जिम्मेदार ठहराते हुए गला काट दिया; आरोपी गिरफ्तार

पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने तलाक के लिए मां को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका गला काट दिया। आरोपित ध्यानेश्वर एस. पवार ने 10 फरवरी की देर रात अपने आवास पर घटना को अंजाम दिया था। वह खड़की गोला बारूद फैक्ट्री में इंजीनियर है। पुलिस अधिकारियों ने उसे शिरडी से गिरफ्तार किया है। रिमांड के लिए उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना है। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ समय पहले उसका तलाक हुआ था। इसके बाद से वह परेशान रह रहा था। वह आवास पर अकेले रहता था।

मुंबई में बढ़ रहे है रियल एस्टेट अपराध

मुंबई। मुंबई में, रियल एस्टेट एक महत्वपूर्ण उद्योग और एक विशाल बाजार है। इस वृद्धि के साथ-साथ, शहर में रियल एस्टेट से संबंधित अपराध भी बढ़ रहे हैं। प्रमुख डेवलपर्स समेत कई बिल्डर लोगों को धोखा देने में शामिल रहे हैं। लगभग हर पुलिस स्टेशन हर कुछ दिनों में डेवलपर्स द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करता है। कई लोगों ने रियल एस्टेट घोटालों में अपनी जीवन भर की बचत खो दी है। हाल ही में, डेवलपर ललित टेकचंदानी को हाउसिंग धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 30 जनवरी को गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने नवी मुंबई के तलोजा में टेकचंदानी की निर्माण परियोजना में ₹36 लाख का निवेश किया था, जहां निर्माण 2017 की समय सीमा से एक साल पहले रुक गया था। एक अन्य घटना में, डेवलपर जयेश विनोद तन्ना को हाल ही में गोरेगांव स्थित एक परियोजना में 27 फ्लैट खरीदारों से ₹40 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मामला आहूजा बिल्डर्स से संबंधित है, जो कथित तौर पर आहूजा बिल्डर्स द्वारा किया गया दो दशक पुराना आवास और निवेश घोटाला है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

विकास की उम्मीद हराम

हिमाचल में विकास को तरसती आंखें आज भी अनिश्चय के संदर्भों में उलझी हैं। जब फोरलेन प्रोजेक्ट ने मंडी का सफर तय किया, लोगों ने जमीन पर बारूद उगा दिया और अब कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के सामने विस्फोट के तौर तरीके बिछा कर सवाल किए जा रहे हैं। लोग तरक्की की फसल काटना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर पांव धरने की इजाजत नहीं देते। उन्हें घर की गली तक वाहन चलाने योग्य सडक चाहिए, लेकिन अपनी दो इंच जमीन देना गंवारा नहीं। उन्हें चौबीस घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति चाहिए, लेकिन न घर के सामने कोई पोल और न ही जमीन से पानी के पाइप गुजरने की मंजूरी देते। लैंड सीलिंग एक्ट ने कई समाज बना दिए। एक वे जो लघु जमींदार थे, उनसे छीनकर जमीन ने एक नए समाज की पैमाइश कर ली। दूसरे वे जिनकी जमीन पर बागीचे खड़े थे, वे अपनी संपत्ति के पूरी तरह मालिक बने रहे। मुजारों में बंटी जमीनों की बोली लगी और मुफ्त के दालान में कृषि योग्य जमीन का मोल तय हो गया। अब जन सुनवाई के मोर्चे पर दलीलें विकास पर इस कद्र भारी हैं कि हिमाचल सिर्फ गुजारे लायक तर्क और मंच के लायक घोषणाएं चुन सकता है। विकास की अपेक्षा में समाज यूं तो राजनीति की चटनी पीस-पीस कर हर बार सत्ता के आशियाने और विपक्ष के खजाने बदल देता है, लेकिन हर सरकार की लागत बढ़ाकर समाज के भीतर सिर्फ फायदे चुनने की तासीर ही पैदा हो रही है। इसी के साथ सामाजिक मंशा में एक स्वघोषित और सियासत से पोषित अतिक्रमण भी है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां की सार्वजनिक जमीन पर डाका न पड़ा हो। ऐसा कोई शहर नहीं जहां की संपत्तियों पर कब्जाधारी न हों। जो समाज कूहलें, खड्डें व नाले चुरा सकता हो, उससे सार्वजनिक विकास की उम्मीद करना भी हराम है। ऐसा तब भी हुआ था जब धूमल सरकार ने एविएशन से जुड़ा एसईजेड ऊना में विकसित करके एक बड़े हवाई अड्डे की परिकल्पना की थी। यह इसलिए क्योंकि वहां की सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमणकारी पनप चुके थे।

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के भीतर कितनी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, कितनी कूहलों और रास्तों की बबार्दी और कितनी लैंड सीलिंग एक्ट से मिली जमीन बिकी है, इसका हिसाब लगाया जाए तो गगल कस्बे में कितने ही एकड़ सार्वजनिक भूमि निकल आएगी। एक सर्वेक्षण यह कर लें कि प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन में कितने बंजर खेत, कितने नए भवन, कितने आवारा पशु और इस इलाके के बाजारों में कितना स्थानीय अनाज बिकता है। हैरानी यह कि हिमाचल में अब कोई ऐसी भूमि नहीं जो हमें भरपेट खिला सके। एयरपोर्ट विस्तार के भीतर खड़ी दुकानों में बाहरी राज्यों से आई दूध की थैलियां, आटे और चावल की बोरियां और तेल की बोतलें बताती हैं कि अब एक दिन बाहरी राज्यों से आपूर्ति न हो तो सारे चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट विस्तार के क्षेत्र में सरकारी व अन्य रोजगार का विश्लेषण करें ताकि मालूम हो कि अब हल की जोत कितनी बची है। बेशक कांगड़ा एयरपोर्ट पुनर्वास के मानक एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। पुनर्वास की बेहतर तस्वीर के तहत काम के बदले काम, व्यापार के बदले व्यापार और आवास के बदले आवास मिलना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सामाजिक सौदेबाजी में विकास का अर्थ गुम हो जाए। बेशक कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की रूपरेखा में आ रहे व्यापारिक संस्थानों को भविष्य की चिंता है, लेकिन इन कस्बों में सडकों को निगल चुके वाहनों या बाजारों तक बिछ गए दुकान के सामान ने कौनसा सदाचार पैदा किया है। बहरहाल जन सुनवाई के शोर में विकास मुजरिम है, सरहद के हिसाब से हर पैमाइश दुश्मन है। विकास दुश्मन है, अगर इसकी जरूरत हमारे आंगन की मिट्टी से मुलाकात करे। विकास दुश्मन है, अगर इसकी बात जंगलात महकमे से करें।

+91 99877 75650

editor@rokthoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुंबई से पालघर का सफर हो सकेगा आसान

वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक की तैयारी में सरकार...

पालघर : आने वाले समय में मुंबई से पालघर का सफर आसान हो सकेगा। महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने वसोर्वा-विरार सी लिंक का विस्तार पालघर तक करने की योजना बनाई है। मुंबई के वसोर्वा से एमएमआर के विरार तक प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय सी ब्रिज के पालघर तक के विस्तारित मार्ग के लिए जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके लिए आरवी एसोसिएट और निप्पोन नामक दो बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई है। एमएमआरडीए जल्द ही इन्हें फाइनल कर डीपीआर का काम सौंपेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सरकार ने वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक के निर्माण का काम एमएसआरडीसी से लेकर एमएमआरडीए को दे दिया है। लगभग 80 किमी लंबा वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज होगा।

79.11 किमी की परियोजना

पहले चरण में मुंबई को सीधे विरार से जोड़ने के लिए 43 किमी लंबे वसोर्वा-विरार सी लिंक के निर्माण की योजना बनी है। अब दूसरे चरण में इसका विस्तार पालघर तक करने के लिए अलग डीपीआर बनेगा। पश्चिमी उपनगरों की ओर जाने वाली 6 लेन कनेक्टिंग सड़कों के साथ पूरी परियोजना 79.11 किमी लंबी होगी। वीवीएसएल को पालघर के समुद्री तट तक जोड़ने के लिए 21.8 किमी लंबी सड़क और उसे पालघर शहर से कनेक्ट करने के लिए 7.3 किमी लंबा कनेक्टर तैयार करना होगा। इसके डीपीआर के लिए जल्द ही एजेंसी फाइनल हो जाएगी। एमएमआरडीए द्वारा प्रस्तावित वसोर्वा-विरार सी लिंक को पालघर तक विस्तारित करने का निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।

होगा सबसे बड़ा सी लिंक

मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले 22 किमी लंबे देश के सबसे बड़े मुंबई ट्रांसहार्बर अटल सेतु पर यातायात शुरू हो गया है। इसके बाद अब मुंबई के पश्चिमी तट पर लगभग 80 किमी लंबा वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज होगा। यह लगभग 1 किमी समुद्र के किनारे के अंदर से होकर जाएगा। एमएमआरडीए अधिकरियों के अनुसार देश के इंफ्रा मार्बल के रूप में यह सी ब्रिज विश्व के 3 सबसे बड़े समुद्री ब्रिज में शामिल होगा। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। एमएमआरडीए नरीमन प्वाइंट और कोलाबा के बीच एक अन्य समुद्री लिंक पर भी काम शुरू करने जा रहा है। बांद्रा से वसोर्वा सी लिंक का काम एमएसआरडीसी के माध्यम से शुरू है।

आवागमन में क्रांतिकारी परिवर्तन

वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक से मुंबई और एमएमआर क्षेत्र के आवागमन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। प्रस्तावित सी ब्रिज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसवी रोड और लिंक रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर यातायात की भीड़ करने के साथ पालघर तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना के तहत चारकोप, उत्तन, मीरा भायंदर, वसई- विरार और नालासोपारा जैसे उपनगरों में कनेक्टर बनेंगे, जिससे कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। वसोर्वा-विरार-पालघर सी लिंक बनने के बाद मुंबई से पालघर तक की 3.30 घंटे की यात्रा घट कर 1 घंटे हो जाएगी। 70 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड 8-लेन (4+4 कॉनफि गरेशन) सड़क बनने से आवागमन आसान हो जाएगा। इस समय मुंबई से विरार और पालघर के उपनगरों को जोड़ने के लिए एकमात्र तेज साधन लोकल ट्रेनें ही हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लोकल के एक विकल्प के रूप में विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

सीट बंटवारा मुद्दे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले

मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस और एमवीए वोट शेयर में आगे रहेंगे, साथ ही वीबीए (वंचित बहुजन आघाडी) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। समाधान किया जाएगा. ''मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस और एमवीए वोट शेयर में अग्रणी रहेंगे, और यह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा हैङ्ग कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के सार्वजनिक एजेंडे में समान विषय हैं, जिसके लिए उन्होंने एक समझ विकसित की है। सीटों का बंटवारा पटोले ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, ''इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।'' इससे पहले 30 जनवरी को, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) को शामिल करने की घोषणा की थी। एक्स पर एक पोस्ट में संजय राउत ने कहा, ''आज वंचित बहुजन अघाड़ी महा विकास अघाड़ी में शामिल हो गया.'' उन्होंने कहा, ''भारत का संविधान खतरे में है। हमें एक साथ आना होगा और संविधान को बचाना होगा।'' संजय राउत ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि वीबीए को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल करने की चर्चा 9 जनवरी को हुई गठबंधन की बैठक के दौरान हुई थी। इससे पहले दिसंबर में, वीबीए (वंचित बहुजन आघाडी) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन को लिखे अपने पत्र में खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रत्येक दलों को 12 सीटों के उनके प्रस्तावित फॉमूर्ले को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

POCSO कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को किया बरी

मुंबई: विशेष POCSO अदालत ने जुलाई 2016 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज 30 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया जब लड़की ने गवाही दी कि उसने अपने सौतेले पिता के साथ घर पर लगातार झगड़े के कारण घर छोड़ दिया था।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता, 12वीं कक्षा की छात्रा, अपनी मां और अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थी। 26 जुलाई 2016 को, जब मां और सौतेले पिता बाहर थे, लड़की ने अपना घर छोड़ दिया। मां ने कांजुरमार्ग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 2 अगस्त 2016 को लड़की को आरोपी के घर पर खोजा गया जो उसका पारिवारिक मित्र था। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। आरोपी को 30 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 15 दिसंबर 2016 को जमानत दे दी गई थी। लड़की ने अपनी गवाही में अपहरण या यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया। दरअसल लड़की ने बताया कि उसके सौतेले पिता को शराब की लत थी और उसके परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे. 26 जुलाई 2016 को वह आरोपी के साथ घर छोड़कर विरार स्थित आरोपी के घर चली गई। वह वहां 7-8 दिन रुकी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, 'पीड़िता के मौखिक साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती अपने घर ले गया है या आरोपी ने पीड़ित लड़की पर किसी तरह का यौन हमला किया है.'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने SRA के सर्कुलर पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया

मुंबई : 6 जून 2015 को स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा जारी एक परिपत्र, जो पुनर्विकास परियोजना के लिए अपना परिसर खाली करने वाले झुग्गीवासियों को डेवलपर द्वारा भुगतान किए जाने वाले पारगमन किराए में नियमित वृद्धि को अनिवार्य करता है, अभी भी जारी है। धूल जमा करना. सर्कुलर इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था कि अक्सर कई पुनर्विकास परियोजनाएं लंबे समय तक अधर में लटकी रहती हैं, जिससे रहने वालों को दशकों तक किराए के परिसर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के ध्यान में लाया गया, जिसने स्लम प्राधिकरण को वडाला के स्लम निवासियों के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जिसके द्वारा उसने परिपत्र को लागू करने की मांग की थी। एक प्रभाग ने कहा, ''हम तीसरे प्रतिवादी, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग एसआरए को याचिकाकताओं

के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करते हैं और जो कि 1 दिसंबर, 2023 को प्राथमिकता के आधार पर और अधिमानतः आज से छह सप्ताह के भीतर दिया गया है।'' 7 फरवरी को जस्टिस गौतम पटेल और कमल खट्टा की बेंच। अदालत वडाला ग्राम कल्याण सीएचएसएल के पात्र 78 झुग्गीवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एसआरए को पारगमन किराए में 5% वृद्धि को अनिवार्य करने वाले परिपत्र को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सीएचएसएल का गठन वडाला में कई छोटी झुग्गी बस्तियों को शामिल करके किया गया था, जिन्हें झुग्गीवासियों के हितों के लिए पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसमें 2,300 से अधिक झुग्गीवासी और नगर निगम के किरायेदार शामिल हैं।

उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थोराट और अधिवक्ता यशोदीप देशमुख ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित पुनर्विकास के बाद कई व्यक्तियों ने डेवलपर मेसर्स मेरिट मैग्नम कंस्ट्रक्शन (जिसे पहले विमल बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था) को अपने परिसर का ''खाली और शांतिपूर्ण कब्जा'' सौंप दिया है।शुरूआत में 2004 में एक डेवलपर नियुक्त किया गया था और किराया 15,000 रुपये तय किया गया था। वर्षों से, कानूनी विवाद थे और पुनर्विकास परियोजना रुकी हुई थी। इसके बाद मेरिट मैग्नम कंस्ट्रक्शन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 31 जुलाई, 2023 को डेवलपर ने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर परिसर खाली करने के लिए एक पत्र और 6 सितंबर को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया। देशमुख ने कहा कि याचिकाकताओं ने 1 दिसंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग को एक अभ्यावेदन दिया था और एक अनुस्मारक पत्र भी भेजा था। हालाँकि, जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने लठ का दरवाजा खटखटाया। इस बीच, डेवलपर ने 19,000 रुपये और एक बार की शिफ्टिंग लागत 20,000 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की। हालांकि, प्रति माह 23,000-25,000 रुपये की बाजार दर को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकताओं ने अधिक किराया मांगा है।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने छोड़ा कांग्रेस हाथ... पार्टी से दिया इस्तीफा...

मुंबईः महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चव्हाण ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले को सौंप दिया है। साथ ही पत्र में चव्हाण ने अपना पदनाम पूर्व विधायक बताया है। पूर्व एमपीसीसी अध्यक्ष ने 1987 से 1989 तक लोकसभा के सांसद के रूप में भी कार्य किया और मई 2014 में निचले सदन के लिए फिर से चुने गए। वह 1986 से 1995 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष और महासचिव थे। उन्होंने 1999 से मई 2014 तक तीन कार्यकालों तक महाराष्ट्र विधान सभा में कार्य किया। उन्होंने 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 9 नवंबर 2010 को, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले से संबंधित

भ्रष्टाचार के आरोप। 2014 के आम चुनावों में, चव्हाण नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए, लेकिन 2019 में सीट हार गए। भाजपा के प्रताप पाटिल चिखलीकर एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस की नैया छोड़ने वाला तीसरा बड़ा नाम हैं। सबसे पहले दक्षिण मुंबई के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा और उसके बाद पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी गए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या चव्हाण बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने रहस्यमय जवाब दिया।

'मुंबई के गोवंडी में बम है' सुनकर दौड़ पड़े पुलिस अधिकारी, जांच में खुलासा... नशे में शख्स ने किया था कॉल

नागपुर : नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम के पास शनिवार (10 फरवरी) को एक फोन आया, जिसमें मुंबई के गोवंडी इलाके में बम होने की सूचना दी गई. इसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए. फोन करने वाले वेंकटेश राजन नाम के शख्स ने पुलिस को बताया कि गोवंडी के देवनार कॉलोनी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बम रखे गए हैं. बम की खबर मिलते ही स्थानीय गोवंडी पुलिस को सूचित किया गया, जब उन्होंने उस स्थान पर जांच की, तो वहां कुछ नहीं मिला. वहीं बाद में जब पुलिस ने फोन करने वाले का नंबर ट्रेस किया और उससे पूछताछ की तो पता चला

कि उसने शराब के नशे में फोन किया था. इसके बाद पुलिस ने वेंकटेश राजन के खिलाफ मामला दर्ज किया और 11 फरवरी को गोवंडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की जांच कर रही है. बता दें कि इसके पहले फरवरी के पहले हफ्ते में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया तो उन्होंने इसकी सूचना सिटी पुलिस और क्राइम ब्रांच अळर को दी. इसके बाद कुछ संदिग्ध जगहों की तलाशी भी ली गई, लेकिन इस दौरान कुछ नहीं मिला. जबकि बीते साल जुलाई में भी मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को ऐसा धमकी भरा मैसेज भेजा गया था. इसमें न सिर्फ मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई थी, बल्कि यह भी कहा गया था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार निशाने पर हैं. इसके बाद पुलिस ने ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 (2) के तहत मामला दर्ज किया था.

सोने की तस्करी पर सीमा शुल्क विभाग ने की कार्रवाई... 4 दिनों में 5 करोड़ से अधिक जब्त !

मुंबई : पिछले चार दिनों में हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने कथित तौर पर तस्करी में शामिल भारतीय और विदेशी यात्रियों से 5 करोड़ रुपये से अधिक का सोना जब्त किया है। इस महीने अब तक हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 12 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का तस्करी का सोना जब्त किया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, 09 फरवरी से 11 फरवरी तक पांच अलग-अलग मामलों में, हवाईअड्डा सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों ने विदेशी और भारतीय नागरिकों से 97 लाख रुपये मूल्य का 1.76 किलोग्राम से

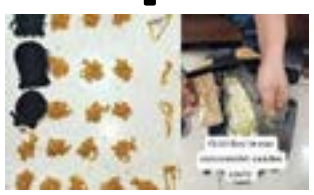

अधिक सोना जब्त किया। यह सोना यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले चेक-इन सामान, कपड़ों और सैंडलों की अंदरूनी परत में छिपा हुआ पाया गया।

7 फरवरी से 09 फरवरी के बीच बनाए गए दस अलग-अलग मामलों में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने 10 मामलों में 4.29 करोड़ रुपये मूल्य का 7.88 किलोग्राम सोना और 16 आईफोन जब्त किए थे। एक सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा, ''इन मामलों में सोना एयरपोर्ट लाउंज के शौचालय में हाउसकीपिंग स्टाफ, जूस पाउडर बॉक्स, सैंडल और बॉडी कैविटी सहित अन्य स्थानों में छिपाया गया था।'' 6-7 फरवरी, 24 को, हवाईअड्डा आयुक्तालय, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III ने पांच अलग-अलग मामलों में भारतीय नागरिकों से 3.49 करोड़ मूल्य का 6.33 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया। सोना शरीर पर, पहने हुए कपड़ों, मोबाइल चार्जर, पर्स, हेयर ड्रायर और चेक इन बैग के कोने की पाइपिंग में छिपाया गया था।

आदित्य ठाकरे ने की बाल ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग

मुंबईः शिव सेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने रविवार को शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की और भाजपा पर बालासाहेब ठाकरे की दोस्ती और योगदान को भूलने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, ''हां हम चाहते हैं (बालासाहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न)। बीजेपी दोस्ती और योगदान भूल गई है अन्यथा वे हमारी पार्टी और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे होते।'' इससे पहले 9 फरवरी को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की थी , जिनका 2012 में निधन हो गया था।

''पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भारतीय हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन

, को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एस स्वामीनाथन का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया। एक वैज्ञानिक जिसने इतना कुछ हासिल किया, उसे अपने जीवनकाल के दौरान ही यह सम्मान मिलना चाहिए था। वैसे भी, राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट किया । अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और प्रणब मुखर्जी को सम्मानित करके राजनीतिक उदारता दिखाई थी, उन्हें वही उदारता दिखानी चाहिए और बालासाहेब ठाकरे को भी ' भारत रत्न ' घोषित करना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''इस देश के एक प्रमुख कार्टूनिस्ट और देश भर के सभी हिंदुओं के गौरव को जगाने वाले एक अद्वितीय नेता इस सम्मान के पात्र हैं।

यह मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए खुशी का क्षण होगा, जिन्हें बालासाहेब के विचार विरासत में मिले हैं।'' शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बालासाहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की। केंद्र सरकार ने इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए पांच नामों की घोषणा की।

मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र इस सप्ताह के अंत में बुलाए जाने की संभावना

मुंबई: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद , आरक्षण के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र इस सप्ताह के अंत में बुलाए जाने की संभावना है, सूत्रों का कहना है कहा। शनिवार को, कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव, अंतरवाली-सरती से एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।

पाटिल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार अगले दो दिनों में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाए। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए मसौदा अधिसूचना को लागू करने के लिए इसे विशेष विधानसभा सत्र में कानून बनाया जाना चाहिए।'' पाटिल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे। इससे पहले, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा करते हुए पाटिल ने कहा, ''फिर से अनिश्चितकालीन भूख

हड़ताल पर बैठने की बहुत जरूरत है । आरक्षण के लिए कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कानून मराठा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब उन्हें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वे विजय रैली करेंगे और उस दिन को 'महा दिवाली' के रूप में मनाया जाएगा। ''पिछले 70 वर्षों में यह पहली बार है कि मराठा समुदाय के पास आरक्षण के लिए एक मजबूत कानून है। हमने मुंबई तक मार्च करने की योजना बनाई थी। जब हमें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम एक विजय रैली आयोजित करेंगे और वह दिन होगा।'' महा दिवाली के रूप में मनाया जाता है,'' उन्होंने कहा।

भले ही राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर मराठा समुदाय को आरक्षण देने का दावा किया है, लेकिन नेताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के बाद जारांगे पाटिल और उनका समुदाय संदेह में हैं। जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालाँकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है। ''मैं पिछले 35 वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुर्जर भी शामिल हो जाएंगे। मजबूत समुदाय इस तरह ओबीसी श्रेणी में प्रवेश करेंगे। हम हर संभव तरीके से लड़ेंगे।'' लोकतंत्र में उम्मीद की जानी चाहिए।

महिलाओं को सक्षम बनाने में जुटी मनपा..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथो देगी सहायता राशि, कर्ज का बोझ होगा कम

मुंबई : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कोस्टल रोड और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर बनने वाले टनल का भूमिपूजन करेंगे। यह दोनो ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुंबई मनपा के है। मनपा प्रशासन मुंबई की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इसी दौरान प्रधानमंत्री के हाथो सहयाता राशि भी देने का निर्णय लिया है। मनपा प्रशासन देश की पहली महानगर पालिका है जो कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं में खुद के पैर पर खड़ा होने के लिए कर्ज लिया है मनपा उन्हे सहायता राशि देकर उनका कर्ज का बोझ हल्का करेगी।

बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में समुद्र के नीचे और समुद्र के किनारे बने कोस्टल रोड की शुरूआत करने का उद्घाटन करेंगे। कोस्टल रोड देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमे समुद्र के नीचे वाहनों के आवागमन के लिए टनल बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह पश्चिम उपनगर से पूर्व उपनगर को जोड़ने वाले गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर गोरेगांव के पास बनने वाले दो टनल का भूमिपूजन करेंगे।यह दोनो ही प्रोजेक्ट मुंबई महानगर द्वारा तैयार किया गया है जिससे मुंबई में होने वाली ट्रैफिक समस्या से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा साथ ही।पश्चिम उपनगर से पूर्व उपनगर तक के आवागमन के लिए एक नया रास्ता बनेगा।मनपा प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे को औचित्य मानते हुए मुंबई की महिलाओं को अपने पैर खड़ा करने के लिए आकांक्षित महिला सशक्तिकरण योजना के तहत बैंको से कर्ज ली हुई महिलाओं का कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। मुंबई मनपा देश की पहली महानगर पालिका है जो कि महिलाओं को अपने रोजगार करने और खुद के पैर पर खड़ा होने के लिए बैंको से लिए कर्ज का बोझ कम करने के लिए सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।

पनवेल में तीखी बहस के बाद पति ने पत्नी पर फेंका एसिड... मामला दर्ज

मुंबई : एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी पर कथित तौर पर तेजाब फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (ए) (एसिड के इस्तेमाल से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि आरोपी रमजान सिद्दीकी गाजी ने 20 जनवरी को पनवेल स्थित अपने घर पर तीखी बहस के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी अमीना खातून (28)

पर तेजाब फेंक दिया। उन्होंने कहा, पीड़िता के चेहरे पर चोट लगी है और उसका पश्चिम बंगाल में उसके गृहनगर में इलाज चल रहा है।अधिकारी ने कहा, उसने पश्चिम बंगाल में बनियापुकुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला पनवेल तालुका पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुंबई में करीब 1000 शिक्षकों की 'इलेक्शन ड्यूटी'... शिक्षक संघों का विरोध, सर्कुलर रद्द करने की मांग!

मुंबई : आगामी चुनावों के मद्देनजर, मुंबई नगर निगम, निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है. हालांकि, राज्य में शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया है. महाराष्ट्र राज्य अध्यापक परिषद की ओर से इस संबंध में जारी परिपत्र को वापस लेने और कार्य में शामिल होने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य न सौंपने का अधिकार होने के बावजूद परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी सौंपी जाने से मुंबई के शिक्षकों में गुस्सा है। इस मामले में, मुंबई में लगभग 1000 शिक्षकों को परीक्षा अवधि के दौरान 'चुनाव ड्यूटी' पर लगाया गया है, इसलिए शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के दौरान गैर शैक्षणिक कार्य दिए जा रहे हैं और

शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है. शिक्षक संघों का कहना है कि इस तरह का काम शिक्षा सीमा अधिनियम का उल्लंघन है.

कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने इस संबंध में अर्जेंट नोटिस भेजकर शिक्षकों को ज्वाइन करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि करीब एक हजार शिक्षकों को भी चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है और अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसलिए शिक्षक संघ उस कार्य के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं और इस सर्कुलर को वापस लेने और इस आदेश को रद्द करने की मांग की है. इस कार्य से पहले, मुंबई नगर निगम के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी पिछड़ा वर्ग आयोग के निदेशों के अनुसार मराठा आरक्षण के संबंध में एक सर्वेक्षण कर रहे थे। यह काम पूरा होते ही अब उन्हें चुनाव ड्यूटी में शामिल होने का आदेश दिया गया है तो छात्रों को कैसे पढ़ाएं? ऐसा सवाल शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com